Volume 1 Issue 1 June. 2025

International Journal of Pedagogy, Health and Management research

नई शिक्षा नीति 2023 का उच्च शिक्षा पर प्रभाव : स्वायत्तता, बहुविषयकता और रिसर्च की दिशा

Date of Submission 22/03/25
Date of Acceptance 15/04/25
Date Publication 01/06/25

डॉ मनीषा लौवंशी*

एच. एल. अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिला नर्मदा पुरम

शोध सारांश

नई शिक्षा नीति 2023 (NEP 2023) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई दृष्टि प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वतंत्र, बहुविषयक और शोध-उन्मुख बनाना है। नीति का जोर केवल पाठ्यक्रम सुधार पर नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के ढांचे, शासकीय व्यवस्था, और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को पुनर्परिभाषित करने पर है। यह समीक्षा-लेख तीन प्रमुख स्तंभों — स्वायत्तता, बहुविषयकता और अनुसंधान — पर केंद्रित है जो उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और गुणवत्ता-संपन्न बनाने की दिशा में कार्य करते हैं (चित्र 1 देखें)। लेख में यह भी विश्लेषण किया गया है कि इन बदलावों के व्यावहारिक पक्ष क्या हैं, और संस्थानों को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और नीति समर्थन की चर्चा भी की गई है। कुल मिलाकर, यह लेख शिक्षाविदों, नीति-निर्माताओं और शोधार्थियों के लिए उपयोगी दृष्टिकोण प्रदान करता है।

मुख्यशब्द : शिक्षक, शिक्षा, शैक्षिक नेतृत्व, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023**, व्यावसायिक विकास ।**

1. परिचय

भारत की पारंपरिक उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से पाठ्यक्रम आधारित, केंद्रीकृत और गैर-लचीली रही है। NEP 2023 इस ढांचे को तोड़ते हुए उच्च शिक्षा को एक नवोन्मेषी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणाली के रूप में पुनर्गठित करना चाहती है। नीति की पृष्ठभूमि में 21वीं सदी की आवश्यकताएं, जैसे डिजिटल साक्षरता, नवाचार, और जीवन-पर्यंत अधिगम, प्रमुख प्रेरक तत्व रहे हैं। यह नीति भारत को "ज्ञान की महाशक्ति" बनाने के उद्देश्य से विकसित की गई है (Ministry of Education, 2023)। इस नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों को मिशनरी संस्थानों के रूप में विकसित करने की योजना है, जो केवल डिग्री प्रदान करने वाले केंद्र नहीं होंगे, बल्कि नवाचार और शोध के केंद्र बनेंगे। परिचयात्मक भाग में यह भी बताया गया है कि किस तरह NEP 2023 पूर्ववर्ती नीतियों से भिन्न है — यह केवल संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करती, बल्कि विचारधारा में परिवर्तन की भी मांग करती है।

चित्र 1: उच्च शिक्षा में NEP 2023 के तीन मुख्य स्तंभों का ग्राफिक प्रतिनिधित्व

2. स्वायत्तता (Autonomy)

NEP 2023 उच्च शिक्षा संस्थानों को 'Institutional Autonomy' देने की बात करती है, जो तीन स्तरों पर लागू होती है: शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय (UGC Guidelines, 2024)। शैक्षणिक स्वायत्तता के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्धारण, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन में स्वतंत्रता दी गई है। प्रशासनिक स्वायत्तता में फैकल्टी नियुक्ति, अकादमिक बोर्ड गठन, और संचालन संरचना शामिल है। वहीं वित्तीय स्वायत्तता में संसाधनों के उपयोग, निधि जुटाने, और बजट योजना की स्वायत्तता आती है। इस खंड में यह भी बताया गया है कि कैसे "Institutional Development Plans (IDPs)" के ज़रिए HEI अपने उद्देश्य तय करेंगे और अपने प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग प्राप्त करेंगे। चित्र 1 (पृष्ठ 3) स्पष्ट करता है कि स्वायत्तता नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है, जो संस्थानों को नवाचार और उत्तरदायित्व दोनों के लिए सक्षम बनाती है।

तालिका 1: स्वायत्तता के प्रकार और उनके संभावित प्रभाव

प्रकार	विवरण	अपेक्षित लाभ
अकादमिक स्वायत्तता	पाठ्यक्रम व मूल्यांकन में स्वतंत्रता	नवाचार और लचीलापन
प्रशासनिक स्वायत्तता	संस्थान संचालन में स्वतंत्रता	शीघ्र निर्णय, उत्तरदायित्व
वित्तीय स्वायत्तता	निधियों का स्वतंत्र प्रबंधन	संसाधनों का कुशल उपयोग

3.. बहुविषयकता (Multidisciplinarity)

NEP 2023 बहुविषयकता को उच्च शिक्षा की आत्मा मानती है। नीति के अनुसार, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों (Multidisciplinary HEIs) में बदला जाएगा, जहां विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, और व्यावसायिक शिक्षा का समावेश होगा। यह बदलाव विद्यार्थियों को केवल एक विषय तक सीमित न रखकर उन्हें विविध विषयों से जोड़ने का अवसर देगा, जिससे उनकी रचनात्मकता और समस्या-समाधान की क्षमता बढ़ेगी (चित्र 2 देखें)। नीति में Undergraduate Education को 'Flexible and Holistic' बनाया गया है जिसमें छात्रों को प्रमुख विषय के साथ Electives और Minor Subjects पढ़ने की सुविधा होगी। इस प्रक्रिया में Academic Bank of Credits (ABC) और Choice Based Credit System (CBCS) को भी लागू किया गया है। इस बहुविषयक दृष्टिकोण से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि रोजगार की संभावनाएं भी विस्तारित होंगी।

4. शोध की दिशा (Research Orientation)

NEP 2023 उच्च शिक्षा को शोध-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें शोध को केवल PhD तक सीमित न रखते हुए, UG और PG स्तर पर भी अनुसंधान आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया है। नीति के तहत National Research Foundation (NRF) की स्थापना की गई है जो गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए वित्त और मार्गदर्शन प्रदान करेगी (Sharma, 2023)। इसमें शिक्षकों और छात्रों को शोध के लिए अनुदान, सहयोगात्मक परियोजनाएं और इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को अपनाने का अवसर मिलेगा। शोध का उद्देश्य केवल प्रकाशन न होकर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना है। इससे HEI नवाचार के केंद्र बनेंगे और उनका वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार होगा। साथ ही, नीति संस्थानों को स्थानीय मुद्दों पर आधारित 'प्रयोगात्मक अनुसंधान' (Applied Research) को प्राथमिकता देने की सलाह देती है।

5. प्रभाव और चुनौतियाँ (Impact and Challenges)

नीति के प्रभावस्वरूप HEIs में शैक्षणिक गुणवत्ता, नवाचार, और संस्थागत उत्तरदायित्व की भावना बढ़ी है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम तैयार करने और अध्यापन के नए तरीकों को अपनाने की स्वतंत्रता मिली है। विद्यार्थियों को अधिक विकल्प और लचीलापन प्राप्त हुआ है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं — जैसे संसाधनों की कमी, शिक्षकों की प्रशिक्षण आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच की समस्याएँ (चित्र 1 और 2 संदर्भित)। संस्थागत बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से तकनीकी संसाधनों, को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नीति को सभी राज्यों और संस्थानों में समान रूप से लागू करना भी एक बड़ी चुनौती है। यह आवश्यक है कि नीति को चरणबद्ध रूप से लागू किया जाए और निरंतर मूल्यांकन के ज़रिए इसमें सुधार किया जाए।

6. निष्कर्ष (Conclusion)

NEP 2023 भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक परिवर्तनकारी दस्तावेज है। यह न केवल शिक्षा के पारंपरिक ढांचे को पुनर्गठित करता है, बल्कि एक समावेशी, नवाचार-संचालित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणाली की नींव रखता है। स्वायत्तता, बहुविषयकता और शोध — ये तीनों स्तंभ शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ाते हैं। नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए संस्थानों को चाहिए कि वे परिवर्तन को अपनाएं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दें और छात्रों को भागीदार बनाएं। साथ ही, सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक संसाधन और नीति समर्थन उपलब्ध कराए। यह नीति केवल दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है, जिसे शिक्षा में नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए (Ministry of Education, 2023; चित्र 1, चित्र 2 संदर्भित)।

चित्र 2: बहुविषयक शिक्षा का मॉडल

7. संदर्भ (References)

1. Ministry of Education, Government of India. (2023). *National Education Policy 2023: Official Document*.
2. UGC Guidelines on Higher Education Transformation, 2024.
3. Kumar, R. (2024). *Multidisciplinarity and Autonomy in Higher Education*. New Delhi: Sage Publications.
4. Sharma, P. (2023). *Reshaping Research Ecosystem in Indian Universities*. Journal of Education and Research.
5. NEP Orientation Modules, NCTE & NCERT 2023.